नवल किशोर सिंह

बनाम

बिहार राज्य

4 अगस्त**, 2004**

[के. जी. बालाकृष्णन और डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, न्यायाधीशगण]

दंड संहिता, *1860:*

धारा *304*-एक विवाद के दौरान अभियुक्तों में से एक ने पीड़ित के पेट में भाला फेंक दिया-चोट लगने से पीड़ित की मौत हो गई- निचली अदालत ने दोनो अभियुक्तों को धारा *302* सपठित धारा *34* में दोषी ठहराया-उच्च न्यायालय ने उनमें से एक को दोषमुक्त कर दिया और दूसरे को धारा *304* में दंडित किया - प्रतिपादित, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से साबित होता है कि अपीलार्थी ने मृतक को चोट पहुंचाई-अदालत दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं थी।

दंड प्रक्रिया संहिता, *1973:*

धारा *113*-अभियुक्त की जाँच करने वाली निचली अदालत-अभियुक्त से केवल तीन सवाल पूछे गए- निवेदन किया गया कि अभियुक्त की ठीक से जाँच न करने में गंभीर त्रुटि थी-प्रतिपादित, उच्चतम न्यायालय अभियुक्त के खिलाफ पूरे साक्ष्य को एक ही प्रश्न में रखने और उसे स्पष्ट करने के लिए कहने की प्रथा की निंदा करता है, क्योंकि अभियुक्त तर्कसंगत और बुद्धिमान स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं हो सकता है-परीक्षण न्यायाधीश को अभियुक्त को साक्ष्य में प्रतिकूल परिस्थितियों को समझाने का अवसर देने के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए था। धारा *313* जांच एक निष्पक्ष सुनवाई का हिस्सा है और इसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए-हालाँकि, अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह याचिका नहीं प्रस्तुत कि वह इस तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रस्त था जिस प्रकार से धारा *313* परीक्षण किया गया था, न्यायालय इस स्तर पर याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

राम शंकर सिंह और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए**.** आई**.** आर**.** ***(1962)*** एस**.** सी**.** ***1239****;* भलिंदर सिंह उर्फ राजू बनाम पंजाब राज्य, ए**.** आई**.** आर**.** ***(1994) 1*** एस**.** सी**.** सी**.** ***726****;* महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह और अन्य, ***[1992] 3*** एस**.** सी**.** सी**.** ***700*** और लल्लू मांझी और अन्य बनाम झारखंड राज्य**,** ***[2003] 2*** एस**.** सी**.** सी**.** ***401,*** पर आश्रित किया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1331/2003

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश आपराधिक अपील संख्या 589/ 1987 दिनांकित 1.8.2002 से।

अपीलार्थी की ओर से उपेंद्र मिश्रा और कन्हैया प्रियदर्शी।

प्रतिवादी की ओर से बी. बी. सिंह और कुमार राजेश सिंह।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया:

एकमात्र अपीलार्थी पर छह अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाया गया और अपीलार्थी और एक अन्य को सत्र न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत दंडनीय हत्या के अपराध के लिए दोषी पाया गया। दोनों दोषी व्यक्तियों ने अपील दायर की और उच्च न्यायालय ने उनमें से एक को दोषमुक्त कर दिया और वर्तमान अपीलार्थी को धारा 304 के तहत दोषी पाया गया और उसे सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

यह घटना 17.11.1974 पर घटित हुई। पीडब्लू-1 लाल देव सिंह का मृत बेटा बैजनाथ सिंह केले के पत्ते काटने में लगा हुआ था।अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थी अन्य सह-अभियुक्त के साथ घटना स्थल पर आया था और वर्तमान अपीलार्थी भाले से लैस था। अभियुक्त व्यक्तियों ने बैजनाथ से पूछा कि वे अभियुक्त के घर के पास केले के पत्ते क्यों डाल रहे हैं। मृतक ने कुछ जवाब दिया। अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि वर्तमान अपीलार्थी ने मृतक बैजनाथ सिंह के पेट में भाला फेंका था। इस बीच, पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और अन्य लोग घटना स्थल पर पहुंचे। पीडब्लू-2 पर भी एक आरोपी ने हमला किया था। घायल बैजनाथ को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पीडब्लू-1 ने बाद में पुलिस को जानकारी दी और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

सत्र न्यायालय में 16 गवाहों से पूछताछ की गई। पीडब्लू 1,2,3 और 8 चश्मदीद गवाह हैं। पीडब्लू-1, मृतक के पिता ने सशपथ बयान दिया कि जब उसका बेटा केले के पत्ते काट रहा था, तो आरोपी वहाँ आया और उसके साथ झगड़ा किया और उसने वर्तमान अपीलार्थी को इस बेटे के पेट पर भाला फेंकते देखा। पीडब्लू-1 के भाई पीडब्लू-2 भी घटना स्थल पर आए और अपीलार्थी को मृतक को चोट पहुँचाते हुए देखा।

अपीलार्थी के वकील ने कहा कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य के बीच कई विरोधाभास हैं। हमें नहीं लगता कि अपीलार्थी के वकील द्वारा बताए गए विरोधाभास उनके साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त हैं, विशेष रूप से, जब इन दो गवाहों की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है।पीडब्लू-2 के चेहरे पर चोट लगी और पीडब्लू 3 और पीडब्लू-8 भी घर में थे और घटना के समय घटनास्थल पर आए थे।पीडब्लू-3 ने सशपथ बयान दिया कि वह देख सकती थी कि उसका बेटा बैजनाथ बागान में काम कर रहा था और अभियोजन पक्ष के पास यह साबित करने के लिए सबूत है कि वर्तमान अपीलार्थी ने मृतक बैजनाथ को चोट पहुंचाई थी।

अपीलार्थी के वकील ने बताया कि सत्र न्यायालय ने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त की ठीक से जांच नहीं करने में गंभीर त्रुटि की हैं। हमारा ध्यान वर्तमान अपीलार्थी से लिए गए बयान की ओर आकर्षित किया गया। अपीलार्थी से केवल तीन प्रश्न पूछे गए थे। पहला सवाल यह था कि क्या उन्होंने गवाहों का बयान सुना और दूसरा सवाल यह था कि गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य से पता चलता है कि उन्होंने मृतक की हत्या की थी और क्या उन्हें बचाव में कुछ कहना था।धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपी से पूछताछ सबसे असंतोषजनक तरीके से की गई थी।धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त को उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने

वाली किसी भी परिस्थिति को समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए था। कम से कम, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विभिन्न वस्तुओं को आरोपी के सामने प्रश्न के रूप में रखा जाना चाहिए था और उसे अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिए था। तत्काल मामले में अभियुक्त को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया था। हम अभियुक्त के खिलाफ पूरे साक्ष्य को एक ही प्रश्न में रखने और उसे समझाने का अवसर देने की प्रथा की निंदा करते हैं, क्योंकि अभियुक्त तर्कसंगत और बुद्धिमान स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं हो सकता है।विचारण न्यायाधीश को अभियुक्त को साक्ष्य में प्रतिकूल परिस्थितियों की व्याख्या करने का अवसर देने के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए था और धारा 313 की परीक्षा को एक खाली औपचारिकता के रूप में नहीं किया जाएगा। पूरा सबूत सामने आने के बाद ही आरोपी अपने बचाव को स्पष्ट करने और अपने खिलाफ सबूत में दिखाई देने वाली परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देने की स्थिति में होगा।अभियुक्त को ऐसा अवसर दिया जाना एक निष्पक्ष सुनवाई जी का हिस्सा है और यदि इसे गलत तरीके से किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप साक्ष्य का अपूर्ण मूल्यांकन हो सकता है।इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में, धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त से पूछताछ के महत्व पर उचित जोर दिया गया था, राम शंकर सिंह और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, AIR (1962) SC 1239; बलिंदर सिंह उर्फ राजू बनाम पंजाब राज्य, [1994] 1 एस. सी. सी. 726; महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह और अन्य, [1992] 3 एस. सी. सी. 700 और लल्लू मांझी और अन्य बनाम झारखंड राज्य, [2003] 2 एस. सी. सी. 401।

वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में कोई तर्क नहीं दिया था कि जिस तरह से धारा 313 का प्रश्न किया गया था, उससे वह गंभीर रूप से पूर्वाग्रहग्रस्त था। यदि धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रक्रिया में इस दोष को इंगित किया गया होता, तो उच्च न्यायालय उचित जांच के लिए मामले को सत्र न्यायालय में भेज सकता था। इस स्तर पर, हम अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, विशेष रूप से जब अभियुक्त यह दिखाने में सक्षम नहीं था कि वह किसी भी तरह से ऐसी अनियमित प्रक्रिया से पूर्वाग्रहित था।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अंत में तर्क दिया है कि सजा के मामले में अपीलार्थी को नरमी दी जा सकती है। अपीलार्थी को सत्र न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया था और उच्च न्यायालय ने इसे आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत में परिवर्तित कर दिया, इसे निर्दिष्ट किए बिना की क्या यह आई. पी. सी. की धारा 304 के भाग I और II के तहत आता है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलार्थी ने क्रूर और क्रूर तरीके से युवा लड़के की मौत का कारण बना। हम उस पर लगाए गए सात साल के कारावास की सजा में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज की जाती है ।

Ashish Kumar